आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
मंगलवार 09.09.2025 समय 1830

मुख्य समाचार :–

- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा – प्रदेश सरकार, हिमालय संरक्षण को लेकर पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
- राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देहरादून में आयोजित तीन दिवसीय वैश्विक सम्मेलन 'हिमालय कॉलिंग–2025' का उद्घाटन किया।
- अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम ने रुद्रप्रयाग जिले में बसुकेदार के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थलीय निरीक्षण किया।
- शिक्षा विभाग में शीघ्र ही आउटसोर्स के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी के 2 हजार 364 पदों पर भर्ती की जाएगी।

हिमालय दिवस

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश सरकार, हिमालय संरक्षण को लेकर पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण काम में सभी को अपनी भूमिका निभानी होगी। हिमालय दिवस के अवसर पर आज देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में राज्य को कई भीषण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा है। इन गंभीर चुनौतियों से प्रभावी रूप से निपटने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों और विशेषज्ञों के बीच समन्वय स्थापित करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि छोटे–छोटे प्रयास, जैसे पानी की बचत, पेड़ों को लगाना और प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना, हिमालय की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसी क्रम में सरकार ने दो से नौ सितंबर तक प्रतिवर्ष हिमालय जन–जागरुकता सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है।

वैश्विक सम्मेलन

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज देहरादून के एक निजी विश्वविद्यालय में आयोजित तीन दिवसीय वैश्विक सम्मेलन 'हिमालय कॉलिंग–2025' का उद्घाटन किया। तीन दिवसीय यह सम्मेलन हिमालय की सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और बौद्धिक धरोहर को समर्पित है, जिसमें देश और विदेश के चिंतक और पर्यावरणविद्, चिंतन और मंथन करेंगे। इस अवसर पर राज्यपाल ने परिसर में हिमालय के उत्पादों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान समय में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, नदियों का प्रदूषण और कंक्रीट के जंगल हमारे अस्तित्व पर प्रश्नचिन्ह खड़े कर रहे हैं। हमें यह समझना होगा कि प्रकृति ने जो दिया है, उसे उसी के स्थान पर रहने देना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हम सभी को इस चेतावनी को समझना होगा और पौधरोपण, जल संरक्षण व पर्यावरणीय संतुलन की दिशा में पहल

करनी होगी। राज्यपाल ने कहा कि 'हिमालय कॉलिंग' हिमालय की रक्षा और संरक्षण के लिए हम सभी की सामूहिक प्रतिबद्धता है।

पर्यावरण संरक्षण

सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आज हिमालय दिवस के अवसर पर लैंसडाउन छावनी क्षेत्र में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर गढ़वाल राइफल्स के जवानों और अग्निवीर रंगरूटों ने भी भागीदारी की। श्री जोशी ने प्रदेशवासियों को हिमालय दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हिमालय हमारे अस्तित्व, संस्कृति और सभ्यता की धरोहर है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की, कि पर्यावरण संरक्षण को जीवन का हिस्सा बनाएं और वृक्षारोपण को एक जन आंदोलन का रूप दें।

नदी महोत्सव गोष्ठी

जल संरक्षण अभियान के तहत चम्पावत में नदी महोत्सव जागरूकता गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी में जल संरक्षण के महत्व, नदियों और नालों की स्वच्छता तथा प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण पर जोर दिया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने सभी सरकारी कार्यालयों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं का निर्माण कर वर्षा जल का संचयन और पुनः उपयोग किये जाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण केवल सरकारी प्रयासों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि प्रत्येक नागरिक को इसके प्रति जागरूक होना होगा।

केंद्रीय टीम रुद्रप्रयाग

अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम, प्रदेश के आपदा प्रभावित जिलों में नुकसान का जायजा लेकर क्षति का आकलन कर रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय टीम ने आज रुद्रप्रयाग जिले में बसुकेदार के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थलीय निरीक्षण किया। अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम के सदस्यों ने बड़ेथ तक सड़क मार्ग से आपदा प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों, प्रशासन व संबंधित विभागीय अधिकारियों से क्षति और पुनर्निर्माण कार्यों के आकलन की जानकारी ली। स्थानीय लोगों ने टीम के समक्ष अपनी समस्याएं रखी और उनके निराकरण का अनुरोध किया। टीम ने स्थलीय निरीक्षण के साथ हवाई सर्वे कर आपदा से प्रभावित क्षेत्रों छैनागाड़ ,तालजमण, बगड़तोक, जौला, डुंगर भटवाड़ी, स्यूर आदि की स्थिति का बारीकी से अध्ययन किया। निरीक्षण के दौरान टीम द्वारा बुनियादी ढाँचे की क्षति, सड़कों, पुलों, सार्वजनिक भवनों, बिजली और जल आपूर्ति लाइनों को हुए नुकसान के आकलन के साथ ही कृषि, फसलों, पशुधन और स्थानीय आजीविका के अन्य साधनों को हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय टीम का नेतृत्व कर रहे संयुक्त सचिव डॉ. आर. प्रसन्ना ने कहा कि उनके इस दौरे का मुख्य उद्देश्य आपदा से हुई वास्तविक क्षति का आकलन करना है, ताकि केंद्र सरकार को प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित क्षेत्रों के लिए आवश्यक सहायता और पुनर्निर्माण कार्यों की योजना शीघ्र बनाई जा सके। उन्होंने कहा कि इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी

जाएगी। इस रिपोर्ट के आधार पर आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, बुनियादी ढाँचे की बहाली और दीर्घकालिक सुरक्षा उपायों के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।

पीएम उत्तराखंड दौरा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 सितंबर को प्रदेश के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा प्रस्तावित है। श्री मोदी हवाई सर्वे के जरिए आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र सरकार, लगातार उत्तराखंड में आ रही आपदा को लेकर निगरानी कर रही है।

चतुर्थ श्रेणी भर्ती

प्रदेश में विद्यालयी शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यालयों और विद्यालयों में लम्बे समय से रिक्त पड़े 2 हजार 364 चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के पदों पर शीघ्र भर्ती की जायेगी। इन सभी पदों को आउटसोर्स के माध्यम से भरा जायेगा, जिसमें स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। कार्मिकों की शीघ्र तैनाती के लिये विभागीय अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गये हैं। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार शिक्षा विभाग में बुनियादी ढ़ांचे के साथ ही मानव संसाधन उपलब्ध कराने में जुटी है। इसी कड़ी में सरकार ने विभाग के विभिन्न कार्यालयों व विद्यालयों में सृजित चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के इन रिक्त पदों– मृत संवर्ग, को आउटसोर्स के पदों में परिवर्तित करने की मंजूरी दे दी है, जिसका शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। आउटसोर्स से तैनात कार्मिकों को प्रत्येक माह 15 हजार रुपये मानदेय दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की नियुक्ति में राज्य में प्रचलित आरक्षण नियमों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

ईको सेंसटिव जोन बैठक

उत्तरकाशी जिले के ईको सेंसटिव जोन में विकास कार्यों और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने कलेक्ट्रेट में एक बैठक ली। बैठक में ईको सेंसटिव जोन में चल रही गतिविधियों, स्थानीय समुदायों की भागीदारी और इन क्षेत्रों में पारिस्थितिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि ईको सेंसटिव जोन में पर्यावरणीय मानकों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और सेंसेटिव जोन में ऐसी परियोजनाएं शुरू की जाएं, जो पर्यावरण के अनुकूल हों और स्थानीय लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक हों। बैठक में ईको सेंसटिव जोन से संबंधित नौ प्रस्तावों पर चर्चा की गई।